इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता

लेखक - हर्ष वी.पंत (प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, किंग्स कॉलेज लंदन)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

8 जुलाई, 2019

"सबसे प्रमुख बने हुए आसियान का इरादा स्पष्ट है, जहाँ यह नीतिगत पहलों के साथ उभरते क्षेत्रीय क्रम का प्रबंधन करना चाहता है।"

जून में बैंकॉक में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के 34वें शिखर सम्मेलन में, इसके सदस्य देश अंततः 'इंडो-पैसिफिक पर आसियान आउटलुक' नामक एक दस्तावेज में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक सामूहिक दृष्टि व्यक्त करने में कामयाब रहे। यह ऐसे समय में आया है जब चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच भू-राजनीतिक प्रतियोगिता बढ़ रही है और इसलिए आसियान के लिए उभरते हुए क्षेत्रीय क्रम में अपनी केंद्रीयता को रेखांकित करने हेतु रणनीतिक पहलुओं को अपने पक्ष में करना अनिवार्य हो गया है।

हालाँकि, शिखर सम्मेलन में आसियान के सदस्य देशों के बीच कई मतभेद थे, लेकिन वे एक गैर-बाध्यकारी दस्तावेज के साथ सर्वसम्मति बनाने में कामयाब रहे। यह दस्तावेज 'एक रणनीतिक और भरोसेमंद क्षेत्र के निर्माण को गति उत्पन्न करने में मदद् करने के लिए एक समावेशी और 'नियम-आधारित रूपरेखा' की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसके आस पास के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनने की प्रतियोगिता के उद्भव के बारे में जागरूकता ने दस्तावेज को विकृत कर दिया है क्योंकि यहाँ तर्क भौतिक शक्तियों के उदय से संबंधित है।

आसियान सदस्य देशों के अमेरिका और चीन से व्यक्तिगत मतभेदों और द्विपक्षीय व्यस्तताओं के बावजूद, ये क्षेत्रीय समूह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में अब एक सामान्य दृष्टिकोण का दावा कर सकते हैं और इस संदर्भ में थाईलैंड के प्रधानमंत्री, प्रयुथ चान-ओशा, ने भी सुझाव दिया है कि उन्हें क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय स्तरों पर सहयोग की मौजूदा रूपरेखाओं को भी पूरा करना चाहिए और क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए ठोस वितरण उत्पन्न करना चाहिए।

चीन सागर में हलचल

दिलचस्प यह भी है कि आसियान सदस्य देश दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता के त्वरित समापन पर जोर देने के लिए सहमत हैं, एक तेजी से लड़ा जाने वाला समुद्री स्थान जो चीन द्वारा बड़े पैमाने पर और फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया द्वारा भागों में दावा किया जाता है। इस जलमार्ग के सैन्यीकरण को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है; जून में, फिलीपींस के मछली पकड़ने वाली नाव चीन के जहाज द्वारा टक्कर मार देने से डूब गई थी। आशा है कि वार्ता के लिए संहिता का पहला मसौदा इस वर्ष के अंत तक आ जाएगा। इन कदमों के साथ, प्रमुख बने हुए आसियान अपने इरादे को स्पष्ट कर रहा है क्योंकि यह चारों ओर भू-राजनीतिक मंथन का प्रबंधन करना चाहता है।

जून में जारी यू.एस. फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (एफओआईपी) रणनीति रिपोर्ट शायद अंतिम प्रयास था, जो इस विषय पर आसियान की चर्चा को एक करीब लाने के लिए आवश्यक था और यह अधिक मुखर चीन के सामने एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। जापान ने 2016 में अपनी स्वतंत्र और मुक्त इंडो-पैसिफिक अवधारणा का पहले ही खुलासा कर दिया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 2017 में अपनी विदेश नीति श्वेत पत्र जारी की थी, जिसमें सुरक्षा, खुलेपन और समृद्धि के आस पास केंद्रित अपनी इंडो-पैसिफिक दृष्टि का विवरण दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में शांगरी-ला संवाद में भारत के भारत-प्रशांत दृष्टिकोण को स्पष्ट किया था, यहाँ तक कि भारत ने इस वर्ष की शुरुआत में विदेश मंत्रालय (MEA) में भारत-प्रशांत विंग की भी स्थापना की थी।

लंबे समय से, आसियान इंडो-पैसिफिक मुद्दे के साथ सामने आने के लिए अनिच्छुक रहा है क्योंकि यह धारणा थी कि यह चीन का विरोध कर सकता है। लेकिन जल्द ही इसका अहसास हुआ कि इस तरह के दृष्टिकोण से अन्य लोग क्षेत्रीय स्थापत्य को आकार दे सकते हैं और खुद आसियान को हाशिए पर रख सकते हैं।

ढांचा

हालांकि, आसियान का दृष्टिकोण इंडो-पैसिफिक को एक निरंतर क्षेत्रीय स्थान के रूप में नहीं देखता है, यह विकास और कनेक्टिविटी पर जोर देता है, जो समुद्री सहयोग, बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी और व्यापक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आसियान संकेत दे रहा है कि वह इस क्षेत्र को प्रमुख शक्ति प्रतियोगिता का मंच बनाने से बचना चाहता है।

यह तथ्य कि आसियान आगे बढ़ चुका है और इंडो-पैसिफिक आउटलुक को स्पष्ट करना अपने आप में चीन के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। लेकिन आसियान के दृष्टिकोण का उद्देश्य चीन को पूरी तरह से इस क्षेत्र के लिए अमेरिका के दृष्टिकोण के साथ संरेखित नहीं करने के लिए प्रेरित करना है।

भारत ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में आसियान के दृष्टिकोण का स्वागत किया है क्योंकि यह क्षेत्र के प्रति अपने दृष्टिकोण के साथ 'अभिसरण के महत्वपूर्ण तत्व' को देखता है। जून में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ की भारत यात्रा के दौरान, भारत ने स्पष्ट किया था कि वह इंडो-पैसिफिक के पक्ष में है लेकिन किसी के खिलाफ नहीं है, वह भू-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में अमेरिका और चीन के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहता है।

भारत-प्रशांत क्षेत्र में निवेश जारी है; जापान के ओसाका में हालिया जी-20 शिखर सम्मेलन के मौके पर, श्री मोदी ने क्षेत्रीय संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार पर ध्यान देने के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ भारत-प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा की थी।

आसियान के साथ अंतत: भारत-प्रशांत में अपनी भूमिका के साथ आने के कारण, मौका अब अन्य क्षेत्रीय हितधारकों के साथ है, जो क्षेत्रीय समूह के साथ काम करने के लिए इस क्षेत्र में शक्ति के संतुलन बनाने के लिए काम करता है जो समावेशिता, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि का पक्षधर है।

GS World टीम...

आसियान

क्या है?

- आसियान (ASEAN] Association of Southeast Asian Nations) या दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन 10 दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों (इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ब्रुनेई एवं लाओस) का क्षेत्रीय संगठन है।
- इसका गठन 8 अगस्त, 1967 को बैंकॉक में 5 देशों- इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने किया था।
- हालांकि, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया जैसे देशों के शामिल होने के बाद सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। गौरतलब है कि आसियान देशों की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है।
- इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है।
- 1994 में आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय फोरम (एशियन रीजनल फोरम) (एआरएफ) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ावा देना था।
- अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान और उत्तरी कोरिया सहित एआरएफ के 23 सदस्य हैं।

पृष्ठभूमि

- ब्रुनेई 1984 में और वियतनाम को 1995 में शामिल किया गया था। फिर, 1997 में लाओस और म्यांमार को इसका हिस्सा बनाया गया।
- 1999 में कंबोडिया को इसका सदस्य बनाया गया। 1976 में आसियान की पहली बैठक हुई। जिसका एजेंडा शांति और सहयोग था।

- 1994 में आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय फोरम की स्थापना की। इसका उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ावा देना था। इसके सदस्य अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान और उत्तरी कोरिया 23 सदस्य हैं।
- 1992 में भारत आसियान का 'क्षेत्रीय संवाद भागीदार' और 1996 में पूर्ण सदस्य बन गया। चीन की भी कोशिश है कि उसे भी आसियान का पूर्ण सदस्य बना जाए।
- 2015 में मलेशिया की राजधानी कुआलालम्पुर में आयोजित इसकी बैठक में आर्थिक नीति पर एक बड़ा फैसला लिया गया।
- जिसमें सभी सदस्य देशों को मिलाकर आर्थिक समुदाय बनाने का फैसला लिया गया। 31 दिसंबर, 2015 में इसको बना भी लिया गया। जिसमें सदस्य कई आर्थिक समझौतों से बंधे हुए हैं।

उद्देश्य

- सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक वृद्धि सामाजिक उन्नति तथा सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना।
- दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को सुनिश्चित करना। आसियान के सदस्य राष्ट्रों को शांतिपूर्वक तरीकों से अपने मतभेदों पर चर्चा करने और समाधान का अवसर प्रदान करना।
- सदस्य राष्ट्रों में सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना।
- आसियान देशों में शैक्षणिक, व्यवसायिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक मामलों में प्रशिक्षण व सुविधाओं के लिए एक-दूसरे को सहायता प्रदान करना।
- दक्षिण पूर्वी एशिया में विकास और सहयोग के लिए आवश्यक शोध और अध्ययन को प्रोत्साहित करना
- समान उद्देश्य वाले विश्व के अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ व लाभकारी संबंध विकसित करना तथा उनके साथ सहयोग हेतु संभावनाओं का पता लगाना।

34वां आसियान शिखर सम्मेलन

- इस बार 34वां आसियान शिखर सम्मेलन थाइलैंड की राजधानी बैंकॉक (bankok) में आयोजित हुआ था।?
- इस बार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के नेताओं ने रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन और दक्षिण चीन सागर विवाद समेत क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।
- आसियान देशों के बीच दक्षिण चीन सागर (south china sea) को लेकर लंबे समय से विवाद है। दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है।
- गौरतलब हो कि आसियान देशों के बीच दक्षिण चीन सागर (south china sea) को लेकर लंबे समय से विवाद है। दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है।

भारत और आसियान

- आसियान और भारत के सहयोग के दूसरे चरण की शुरुआत तब हुई, जब 2001 में दोनों ने आपसी सहयोग को उच्च स्तर पर गति प्रदान करने के लिए नियमित वार्षिक शिखर सम्मेलन के आयोजन का निर्णय लिया।
- इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2002 में कंबोडिया के शहर नामपेन्ह में प्रथम भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तब से लेकर अब तक प्रतिवर्ष भारत, आसियान शिखर सम्मेलन नियमित रूप से संपन्न हो रहे हैं।
- भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2017 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित किया गया था।
- गौरतलब हो कि मोदी ने आसियान के सभी देशों को 26 जनवरी, 2018 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया था। इसके पहले भी भारत ने दिसंबर, 2012 में संबंधों की वर्षगांठ के अवसर पर भारत में भारत-आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. आसियान के सन्दर्भ में निम्नलिखत कथनों पर विचार कीजिए:-

1. इसका गठन 8 अगस्त, 1967 को बैंकॉक में 5 देशों ने मिलकर किया था।
2. 1994 में आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय फोरम की स्थापना की।
3. 34वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक में किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. In the context of ASEAN, consider the following statements-

1. It was established by 5 countries together on 8 August, 1967 in Bangkok.
2. ASEAN established Asian Regional forum in 1994.
3. 34th ASEAN summit has been established in Bangkok.

Which of the above statement is /are correct?

(a) 1 and 2 (b) 2 and 3
(c) 1 and 3 (d) All of the above

Expected Questions (Mains Exams)

प्रश्न: अमेरिका-चीन के बीच तनाव के मद्देनजर हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में आसियान की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

(250 शब्द)

Q. Explain the role of ASEAN in Indo-Pacific region in view to rising tension between America and China.

(250 Words)

नोट : 6 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।

Committed To Excellence